

कलेक्टर की दो टूक: आंगनबाड़ी एवं स्कूलों के जर्जर भवनों को त्वरित रूप से कराएं डिसमेंटल

किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित विभाग होंगे जिम्मेदार



पायनियर संवाददाता < बालोद
www.dailypioneer.com

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा को पूरा करने और शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कमर कस ली है। लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही है। इसी क्रम में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने शुक्रवार को नगर पंचायत गुंडरदेही के सभाकक्ष में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का निर्धारित समयवधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आम जनता के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक, एसडीएम प्रतिमा ठाकरे झा, तहसीलदार गोविंद ध्व, चन्द्रशेखर चन्द्राकर, जयपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य

निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देवे- कलेक्टर

बैठक में कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लक्षित आवासों की जानकारी लेते हुए पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत आवास के कार्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आवास प्लस सर्वे कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए महिला स्व सहायता समूह को अधिक से अधिक आर्थिक एवं आजीविकामूलक गतिविधियों से जोड़ने को कहा। इसके अलावा उन्हें मशरूम उत्पादन, फूलों की खेती, मछली पालन हेतु माकेटिंग की व्यवस्था के लिए प्रेरित करने को कहा। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से विद्यार्थियों के लिए गणवेश की उपलब्धता, शिक्षकों की पदस्थापना की जानकारी के अलावा अध्ययन-अध्यापन तथा अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी ली। शाला भवनों की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त कक्षा निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।

अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में दिव्या उमेश मिश्रा ने राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग, वन, कृषि, पशु चिकित्सा विभाग, खाद्य एवं अन्य विभागों के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आदि कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की।

मोसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करें

कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं स्कूलों के जर्जर भवनों को त्वरित रूप से डिसमेंटल कराएं, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने सभी शालाओं में शौचालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए वर्षा ऋतु के मद्देनजर जलजनित एवं अन्य मोसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उन्होंने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के अलावा पूरे समय चिकित्सकों एवं अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में उन्होंने टीबी उन्मूलन कार्य, म, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वय वंदना कार्ड निर्माण आदि कार्यों की भी समीक्षा की। वन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सघन वृक्षारोपण अभियान हेतु निर्धारित योजना के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिक से अधिक पौधरोपण कर उनके सुरक्षा के उपाय भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए गुंडरदेही विकासखंड में खाद-बीज की समुचित उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को खाद-बीज का प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशु चिकित्सा विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय निकायों के कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की और दिशा निर्देशित किया।

किसान पंजीयन कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश

राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने राजस्व अधिकारियों से राजस्व प्रकरणों के निराकरण के स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्कूली बच्चों के जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में शत प्रतिशत बच्चों का जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु कैंप का आयोजन सुनिश्चित करें। उक्त प्रमाण पत्रों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना बच्चों और उनके परिजनों को न करना पड़े। इसके लिए उन्होंने राजस्व एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से किसान पंजीयन के कार्य की जानकारी लेते हुए इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 5 से 15 जुलाई तक लगेगी शिविर

पायनियर संवाददाता < गरियाबंद
www.dailypioneer.com

गरियाबंद जिले के जनजाति बाहुल्य इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और इलाज की बेहतर सुविधाओं जैसे मूलभूत जरूरतों को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। गरियाबंद जिले के 334 ग्राम को इस अभियान में शामिल किया गया है। इनमें विकासखंड गरियाबंद अंतर्गत कुल 126 ग्राम, मैमपुर अंतर्गत कुल 144 ग्राम, छुआ अंतर्गत 50 ग्राम, फ़ीमेक्षर अंतर्गत 05 ग्राम एवं विकासखंड-देवभोग अंतर्गत 09 ग्राम शामिल है। इन 334 ग्रामों के कल्याण एवं संवर्धन के लिए कलेक्टर श्री बी एस खंडे के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार कार्ययोजना बनाकर संबंधित विभागों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन गांवों में शासन की विभिन्न योजनाओं से शत-प्रतिशत लोगों को लाभान्वित करने के लिए 05 जुलाई से 15 जुलाई तक धरती आबा संतुषिकरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविर में ग्रामीणों को 17 विभागों की 25 योजनाओं से यथासंभव मौके पर ही लाभान्वित किया जाएगा। यह शिविर छुआ विकासखण्ड अंतर्गत 05 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन परसदारखुर्द में आयोजित

होगा। इसी प्रकार 06 जुलाई को ग्राम पंचायत कनसिंघी में, 07 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन पेण्ड्रा में, 08 जुलाई को ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी में एवं 09 जुलाई को ग्राम पंचायत कोसमी में शिविर लगेगी। देवभोग विकासखण्ड अंतर्गत 11 जुलाई को ग्राम पंचायत बरबहली, 12 जुलाई को ग्राम पंचायत घोघर व 13 जुलाई को सुकलीभाटा में शिविर लगेगी। फ़ीमेक्षर विकासखण्ड अंतर्गत 14 जुलाई को ग्राम पंचायत भेंडरी में, 15 जुलाई को ग्राम पंचायत बोड़की में, गरियाबंद विकासखण्ड में 05 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन पंसीपानी में, 06 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन डुमरबाहरा में, 07 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन फुलकां में, 08 जुलाई को ग्राम पंचायत मजकण्ड, 09 जुलाई को ग्राम पंचायत छिंदौला, 10 जुलाई को पतौरादर, 11 जुलाई को जंगलधवलपुर, 12 जुलाई को आमामोरा, 13 जुलाई को कस, 14 जुलाई को कोचवाय में, 15 जुलाई को कोसमी में और मैमपुर विकासखण्ड में 05 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन देहारागुड़ा, 06 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन तुहामेटा, 07 जुलाई को ग्राम पंचायत दबनई में, 08 जुलाई को कोकडी, 09 जुलाई को बोईगांव, 10 जुलाई को फरसरा में, 11 जुलाई को इदगांव में, 12 जुलाई को मंदगमड़ में।

ग्राम कपरमेटा एवं कामता में आयोजित शिविर में हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित

7 जुलाई को गुरुर ब्लॉक के ग्राम अर्जुनी में आयोजित होगा शिविर
पायनियर संवाददाता < बालोद
www.dailypioneer.com

केन्द्र सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं और अन्य सुविधाई ढाँचों को परिपूर्णता प्रदान करने तथा उनके व्यक्तिगत अधिकारों से परिपूर्ण करने के उद्देश्य से जिले में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत लाभ संतुषि शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शु. वार को गुरुर ब्लॉक के ग्राम कपरमेटा एवं डोण्डी ब्लॉक के ग्राम कामता में आयोजित लाभ संतुषि शिविर में आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। ग्राम कपरमेटा शिविर में उपस्थित 3 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 2 हितग्राहियों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित



करने के अलावा ग्रामीणों का सिकलिन जॉच सहित शिविर में पहुँचे ग्रामीणों का टीकाकरण भी किया गया। इसके अलावा शिविर में उपस्थित ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की गईं। इसी तरह ग्राम कामता में आयोजित शिविर में सगरी बाई एवं सुनीता बाई को राशन कार्ड, सविता बाई एवं ललिता बाई को जॉच कार्ड एवं चंद्राम कुन्हारे एवं रोमिन बाई को कोढ़े बीज का वितरण किया गया। इसके अलावा यशोदा बाई एवं रजऊ राम को

मुख्यमंत्री पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही आयोजित लाभ संतुषि शिविर में 50 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड, 3 हितग्राहियों को किसान सम्मान निधि, 4 हितग्राहियों को पेंशन योजना से लाभान्वित करने के अलावा 14 ग्रामीणों का सिकलिन जॉच सहित शिविर में पहुँचे ग्रामीणों का टीकाकरण भी किया गया। इसके अलावा शिविर में उपस्थित ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की गईं।

सहयोगी संघटना के नाते राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ भी आंदोलन में सहभागी बनकर आठवें वेतनमान हेतु कमेटी की गठन करने अभियान में शामिल है। मध्यप्रदेश के चित्रकूट में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के 11 जनवरी के राष्ट्रीय बैठक यह निर्णय भी लिया गया है कि अगस्त 2024 में एनपीएस के स्थान पर लागू की गई पेंशन योजना यूपीएस को भी निरस्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु भी केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि यूपीएस में कर्मचारियों के कंट्रिब्यूशन का अधिकांश हिस्सा सरकार अपने पास रखेगी और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली लाभों में अनेक कटौती की गई है। इसे लेकर देश भर के कर्मचारियों में घोर अस्तोष है।ज्ञापन मे और प्रमुख मांगों(1) केंद्र के समान माह जनवरी 2025 से होगी दो प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स राशि सहित प्रदान की जाए (2) मध्य प्रदेश राज्य की भाति महिला कर्मचारियों को वर्ष में सात दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने कार्ययोजना तैयार

पायनियर संवाददाता < बेमेतरा
www.dailypioneer.com

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस.एस. टूटेजा के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्र बेमेतरा में कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा, कर्वंधा एवं मुंगेरी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन जिले में खरीफ रबी एवं ग्रीष्मकालीन मौसम में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं मछली पालन क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों के प्रसार और समस्याओं के समाधान हेतु कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जी.पी. आयाम, वैज्ञानिक, निदेशालय विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा की गई। उन्होंने बैठक की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों से तकनीकी सुझाव साझा करने की अपील की। कार्यक्रम के शुभारंभ में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तोषण कुमार ठाकुर (केवीके बेमेतरा) ने स्वागत भाषण देते हुए कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका



को किसान और अनुसंधान के मध्य सेतु के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि विज्ञान और अनुसंधान के साथ समन्वय बनाकर नये नवाचारों को अपनाया चाहिए। बैठक के मुख्य अतिथि डॉ. संदीप भंडारकर, अधिष्ठाता, रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, ढोलिया बेमेतरा ने छत्तीसगढ़ की दलहन एवं तिलहन फसलों की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी और फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। विशेष अतिथि डॉ. राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि कृषि समय

आधारित प्रक्रिया है, अतः उन्नत बीज, जैव उर्वरक, बायोपेस्टीसाइड व अन्य कृषि आगनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। डॉ. एस.आर.के. सिंह, निदेशक, कृषि तकनीक अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी), आई.सी.ए.आर., जबलपुर ने प्रदेश में पारंपरिक दलहन व तिलहन फसलों को बढ़ावा देने हेतु जलवायु अनुकूल किस्मों के चयन और कार्ययोजना निर्माण पर बल दिया। तकनीकी सत्र के दौरान केवीके बेमेतरा, कर्वंधा एवं मुंगेरी के प्रमुख वैज्ञानिकों डॉ. बी.पी.

त्रिपाठी, तोषण कुमार ठाकुर व डॉ. एस.के. लहरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही प्रस्तावित कार्ययोजनाओं पर विभागीय अधिकारियों और समिति सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए एवं पशुधन संरक्षण, सीमित चांगगाह, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, पारंपरिक फसलों के प्रोत्साहन हेतु अनुदान व योजनाएं लागू करने संबंधी सुझाव रखे। बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकगण डॉ. प्रदीप सिंह, ईजीटी.एस. सोनवानी, डॉ. रजनी अगसे, डॉ. प्रमीला जोगी, डॉ. एन.सी. बंधारा, नेहा लहरे, डॉ. जितेन्द्र जोगी, डॉ. थानेश्वर देवाना, इजी. पक्खी पोते, डॉ. लव कुमार, डोमन सिंह टेकाम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी सुमन सिंह पैकरा, देशराज यादव, सुष्मिता कंवर, डॉ. पुष्पराज खटकर, डॉ. नूतन पंच्यांबडे, दीपा कहरा, निलेश चंद्रवंशी, सुंदर वर्मा, अमित वर्मा सहित 70 से अधिक अधिकारी और प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।

आठवें वेतन आयोग के घोषणा को अमल में लाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संघ बेमेतरा ने सौपा झापन

पायनियर संवाददाता < बेमेतरा
www.dailypioneer.com

आठवें वेतनमान के कमेटी की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर देशव्यापी आंदोलन के तारतम्य में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है, इसी दौरान 03 जुलाई को सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है बेमेतरा में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रतापध्वज अरुण तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री बोधी राम निषाद, प्रदेश महामंत्री ए के चेलक, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिसिंह राणा और जिलाध्यक्ष बेमेतरा नालेश्वर साहू ने दी है। जारी विज्ञप्ति में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन मंत्री बोधी राम निषाद ने आगे बताया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग गठित करने का प्रावधान को केन्द्र सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वर्ष 2016 से सातवें वेतन आयोग लागू किया गया है, उस हिसाब से 2026 में आठवें वेतनमान लागू होना है, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा 8 वेतनमान के लिए केवल कमेटी गठन करने घोषणा किए है इस दिशा में कोई



कार्यवाही नहीं किया जा रहा है अतः केन्द्र सरकार को जगाने पूरे देश में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठनों द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संघटना के नाते राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ भी आंदोलन में सहभागी बनकर आठवें वेतनमान हेतु कमेटी की गठन करने अभियान में शामिल है। मध्यप्रदेश के चित्रकूट में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के 11 जनवरी के राष्ट्रीय बैठक यह निर्णय भी लिया गया है कि अगस्त 2024 में एनपीएस के स्थान पर लागू की गई पेंशन योजना यूपीएस को भी निरस्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु भी केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि यूपीएस में कर्मचारियों के कंट्रिब्यूशन का अधिकांश हिस्सा सरकार अपने पास रखेगी और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली लाभों में अनेक कटौती की गई है। इसे लेकर देश भर के कर्मचारियों में घोर अस्तोष है।ज्ञापन मे और प्रमुख मांगों(1) केंद्र के समान माह जनवरी 2025 से होगी दो प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स राशि सहित प्रदान की जाए (2) मध्य प्रदेश राज्य की भाति महिला कर्मचारियों को वर्ष में सात दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष के प्रयास से जिले के स्कूलों में भवन की हुई स्वीकृति



पायनियर संवाददाता < बालोद
www.dailypioneer.com

नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होते ही स्कूलों की कमियां उभरने लगी है, ऐसे में बालोद जिले में कई स्कूल मौजूद हैं जिसे निर्माण हुए कई साल हो चुके हैं लेकिन उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। जिसके चलते स्कूली बच्चों को पढ़ाई करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों की

इसी समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री से चर्चा कर उन्हें अवगत कराया जिसके बाद में अब बालोद जिले के चार स्कूलों के लिए सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू ने जब स्कूल शिक्षा मंत्री से चर्चा की और जिले के जर्जर स्कूलों के विषय में उनका ध्यानाकर्षण कराया।

उसके बाद मंत्री ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। जिसके बाद जिले के शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल जगन्नाथपुर सांकरा, शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल पीपरछेड़ी, शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल गुरुर और शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल कमकापर इन चारों स्कूलों के लिए अलग अलग 1 करोड़ 21 लाख रुपये स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकृत किये हैं।

नये सिरे से बनेगा स्कूल

जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू ने सरकार की ओर से राशि स्वीकृत किये जाने के बाद सरकार का आभार जताया और कहा कि बालोद जिले के चार स्कूल जहां स्कूली बच्चों के पढ़ाई करने के लिए भवन ही नहीं था जल्द अब बच्चों को सुविधा मिलने वाली है। क्योंकि सरकार की ओर से स्वीकृत राशि के बाद जर्जर स्कूल भवन को डिसमेंटल किया जायेगा जिसके बाद नये सिरे से स्कूल भवन बनकर तैयार होगा

आंदोलन का अपनाया था रास्ता

बीते वर्ष पीपरछेड़ी गांव के ग्रामीण स्कूली बच्चों के साथ स्कूल में तालाबंदी कर जर्जर स्कूल भवन को नये सिरे से तैयार करने की मांग की थी। जिसके बाद प्रशासन की ओर से महज आश्वासन ही मिल पाया था। इसके अलावा जगन्नाथपुर सांकरा के ग्रामीण भी स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को लेकर प्रशासन से नाराज थे और आंदोलन की चेतावनी दिये थे। लेकिन स्कूली बच्चों की समस्याओं को देखते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने पहल की और आज सरकार की ओर से राशि स्वीकृत कर दी गई।

जिप उपाध्यक्ष ने किया था निरीक्षण

जैसे ही जिले के जर्जर स्कूलों की जानकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू को लगी उसके बाद से ही तोमन साहू सहित मंडल अध्यक्ष धर्मेद साहू, अरुण साहू जिला पंचायत सदस्य पूजा साहू, जयपद सदस्य दमयंती हरदेत, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश निर्मलकर शाला विकास एवं प्रबंधन समिति अध्यक्ष भूपत बघेल, ग्राम सरपंच लता बाई चुरेद, ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी सरपंच कृष्णा राम साहू, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अध्यक्ष श्रवण साहू, भाजपा महामंत्री पुनम चंद जैन, प्रीतम देशमुख ने स्कूलों का निरीक्षण कर जिला लिखा था और फिर स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। सरकार को इस फैसले के बाद ग्रामीणों और स्कूली बच्चों में हर्ष है।

“अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों / छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना” वर्ष 2025-26 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित			
राज्य शासन वलद द्वारा राज्य के होनहार किन्तु अर्थाभावग्रस्त युवा कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण/शिक्षा के लिए राज्य के ऐसे छात्र/छात्राएँ जो संगीत, नृत्य, प्रदर्शनकारी कला विधा में शिक्षा/उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत, गुरुशिष्य परंपरा के तहत पारंपरिक लोक कलाएं सीखने वाले बच्चों तथा संस्कृति संचालनालय द्वारा प्रमुख छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित कलाकारों छात्रों को महत्वपूर्ण विधा के अनुभू मारिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करने के उद्देश्य से “अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों / छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना 2021” स्थापित किया गया है, जिसके लिए प्रविष्टियां आवश्यक दस्तावेज आमंत्रित किया जाना है।			
1. छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के लिए निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियां पंजीकृत डॉक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।			
2. प्रदर्शनकारी कला/विधा एवं अ्य विधाएं-			
क्र.	विधाएं	अ्य विधाएं	
01	लोक/पारंपरिक जनजातीय कलाएं	छत्तीसगढ़ की समस्त पारंपरिक जनजातीय और लोक नट्य, नृत्य, गीत/संगीत, खेल, चरनी, गरीबी, गरीबी-चंद, पंडवनी, चोटल घाटा, भनकल जंगार तथा छत्तीसगढ़ की अन्य पारंपरिक लोक जनजातीय गाथाएं, वाद्य, पाक कला, सौंदर्यकला, गायन, वादन आदि।	
02	शास्त्रीय संगीत	हिन्दुस्तानी (गायन/वादन) एवं केर्नाटक (गायन/वादन) आदि।	
03	शास्त्रीय नृत्य तथा नृत्य संगीत	भारतनाट्यम्, कथक, कुचिपुडी, मोहनीअट्टम, ओडिसी, मण्डीपुरी, कथकली, ओडिसी नृत्य और संगीत आदि।	
04	रामंच	हिन्दी और छत्तीसगढ़ी नट्य मंचन, नाचा, भारा नाट तथा अन्य लोक जनजातीय नट्य विधा सहित	
05	दृश्य कला	ग्राफिक्स, मूर्तिकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, म्यूपाण्ड तथा मृणाला (Ceramics) छत्तीसगढ़ के विविध लोक जनजातीय परंपराओं के चित्राकन की विधा आदि।	
06	सुगम शास्त्रीय संगीत	ठुमरी, ददरा, टप्पा आदि, कव्वाली, गजल आदि।	
3. पात्रता/सामान्य शर्तें-			
■ छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हों; आवेदक की आयु 15 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो;			
■ आवेदक अथवा उनके परिवार की वार्षिक आय रुपये 72,000/- से अधिक न हो;			
■ चिहारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है एवं विधा, निर्माण प्रोत्साहन वस्तुगत राशि 5000/- से अधिकतम राशि 10000/- होगी तथा प्रोत्साहन राशि डिमांड ड्राफ्ट-ई-मेड के माध्यम से देय होगी।			
■ प्रोत्साहन योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cgculture.in पर भी देखी जा सकती है।			
■ प्रविष्टियां / प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 है। प्रविष्टियों के लिए लिफाफे में निम्न- “अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना” वर्ष 2025-26 स्थ अंकित किया जावे। प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों के संबंध में कोई भी पत्रचार मान्य नहीं होगा।			
G-252601992/6			संचालक संस्कृति एवं राजभाषा

